LOK SABHA DEBATES

(Part I — Proceedings with Questions and Answers)

The House met at Eleven of the Clock

Wednesday, February 04, 2026 / Magha 15, 1947 (Saka)

HON'BLE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri N. K. Premachandran

Shri Jagdambika Pal

Shri P. C. Mohan

Shrimati Sandhya Ray

Shri Dilip Saikia

Kumari Selja

Shri Raja A.

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Krishna Prasad Tenneti

Shri Awadhesh Prasad

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Wednesday, February 04, 2026 / Magha 15, 1947 (Saka)

CONTENTS | PAGES

ORAL ANSWER TO STARRED QUESTION (S.Q. NO. 61)	1 – 30
WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 62 – 69, 71 – 80)	31 – 50
WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS (U.S.Q. NO. 691– 738, 740 – 766, 768 – 797, 799 – 832, 834 – 847, 849 – 861, 863 – 920)	51 – 280

Uncorrected – Not for Publication **LSS-D-II**

सत्यमेव जयते

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Wednesday, February 04, 2026 / Magha 15, 1947 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Wednesday, February 04, 2026 / Magha 15, 1947 (Saka)

C ON T E N T S **P A G E S**

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION	**281**
PAPERS LAID ON THE TABLE	**281 - 87**
COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS	**287**
36th to 38th Reports	
STATEMENT RE: INDIA – USA BILATERAL TRADE AGREMENT	**288 - 90**
Shri Piyush Goyal	
…	**291 - 92**
MATTERS UNDER RULE 377 – LAID	**293 - 306**
Shri Mukeshkumar Chandrakaant Dalal	**293**
Shrimati Shobhanaben Mahendrasinh Baraiya	**294**
Shri Pradeep Purohit	**294**
Shri Ashok Kumar Rawat	**295**
Shrimati Bharti Pardhi	**295**
Shri Bhartruhari Mahtab	**296**
Shri Rudra Narayan Pany	**297**
Shri Ganesh Singh	**297**
Shri Lumbaram Choudhary	**298**
Shri Anup Sanjay Dhotre	**298**

Shri Dilip Saikia	299
Shri Suresh Kumar Kashyap	299
Shri Atul Garg	300
Shri Shafi Parambil	300
Shri Ummeda Ram Beniwal	301
Shri S. Supongmeren Jamir	301
Sushri S. Jothimani	302
Shri M. K. Raghavan	302
Shri Sanatan Pandey	303
Shri Utkarsh Verma Madhur	303
Shri Yusuf Pathan	303
Shrimati June Maliah	304
Shri Murasoli S.	304
Shri Lavu Sri Krishna Devarayalu	305
Shri Ramprit Mandal	305
Shri Raja Ram Singh	306
Dr. Rajkumar Sangwan	306
Shri N.K. Premachandran	306

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS 307 - 11
(Contd. -- Inconclusive)

Shri G.M. Harish Balayogi	307 - 08
Dr. Nishikant Dubey	309 - 10
Shri P.P. Chaudhary -- (Speech Unfinished)	311

xxxx

(1100/YSH/HDK)

(प्रश्न 61)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार ने गरीब कल्याण योजना के तहत बहुत अच्छा काम किया है। … (व्यवधान) मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से केवल एक प्रश्न है कि इसको इफेक्टिव करने के लिए, गरीबों तक इसे पहुंचाने में कोई लूपहोल्स न हों, उसके लिए भारत सरकार क्या प्रयास कर रही है?… (व्यवधान)

1101 बजे

(इस समय डॉ. मोहम्मद जावेद, सुश्री महुआ मोइत्रा और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है। … (व्यवधान) वर्ष 2014 के बाद माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने पूर देशभर के सभी 36 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में एनएफएसए लागू किया गया है। … (व्यवधान) 81.356 करोड़ लाभार्थियों को उसका कवरेज दिया गया है। कोरोना के समय में भी 'प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' के तहत गरीब, जरूरतमंद और कमजोर परिवारों को आर्थिक संकट के समय भोजन की कमी से बचाया है। … (व्यवधान) 'प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' के तहत नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार ने 80.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त में राशन दिया है। … (व्यवधान) यह विश्व का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है। यह संख्या पूरे यूरोप की जनसंख्या से भी ज्यादा है। … (व्यवधान) इसके अलावा हमारी सरकार ने एनएफएसए को लाभ-लक्षित आबादी तक कुशलतापूर्वक पहुंचाया है। … (व्यवधान)

'प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' को प्रभावी बनाने के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं। डिजिटलीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। … (व्यवधान) 100 प्रतिशत राशन कार्ड्स का डिजिटलीकरण कर दिया गया है। 99.8 परसेंट फेयर प्राइस शॉप्स पर ई-पीओएस लगाया गया है। 99.9 परसेंट राशन कार्ड्स आधार से लिंक्ड हैं और 99.2 परसेंट लाभार्थी आधार से जुड़े हुए हैं। … (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संथाल परगना में जो जिले गोड्डा, दुमका और देवघर हैं, उनमें माइग्रेंट वर्कर्स की बहुत बड़ी समस्या है और माइग्रेंट वर्कर्स जब शिफ्ट होते हैं तो उनको गरीब कल्याण योजना में राशन लेने में असुविधा होती है। … (व्यवधान) उसके लिए भारत सरकार ने क्या प्लान बनाया है? … (व्यवधान)

(pp. 3-30)

श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मोदी जी की सरकार ने 80.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त अनाज देने का काम किया है। … (व्यवधान) 'वन नेशन वन राशन कार्ड' से देशभर में पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित हो पाई है। … (व्यवधान) अप्रवासी वर्कर्स देश में कहीं से भी ई-पीओएस के माध्यम से अपना राशन ले सकते हैं और इनके परिवारजन भी अपने घर पर अनाज ले सकते हैं। … (व्यवधान) 'वन नेशन वन राशन कार्ड' सभी 36 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू है, जो कि पूरी एनएफएसए आबादी को कवर करता है। अभी तक 201 करोड़ 'पोर्टेबिलिटी' लेनदेन हुआ है। … (व्यवधान) माइग्रेंट परिवारों को 469 एमएलटी अनाज डिलीवर किया गया है। हर महीने 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग 'वन नेशन वन राशन कार्ड' से राशन ले रहे हैं। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यह प्रश्न काल है। मेरी माननीय सदस्यों से अपेक्षा है कि वे प्रश्न काल में माननीय सदस्यों को बोलने दें।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप सदन नहीं चलने देना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सदन में मर्यादित आचरण और व्यवहार करना सभागृह में सभी माननीय सदस्यों की जिम्मेदारी है। इसलिए मेरा आग्रह रहता है कि सभा में मर्यादित आचरण हो, मर्यादित व्यवहार हो। यह सभागृह आप सबका है। इसकी मर्यादा और गरिमा को बनाए रखना आप सबकी जिम्मेदारी है।

… (व्यवधान)

(1105/STS/PS)

माननीय अध्यक्ष : आप अगर प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते हैं, तो सदन की कार्यवाही आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1105 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1200/MM/SNL)
1200 बजे

लोक सभा बारह बजे पुनः समवेत् हुई।
(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1200 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ माननीय सदस्यों, श्री वीरेन्द्र सिंह, सुश्री इकरा चौधरी, श्री अरविंद गणपत सावंत, श्री टी. आर. बालू, श्री के.सी. वेणुगोपाल, श्री कोडिकुन्नील सुरेश, श्री बैन्नी बेहनन, श्री मनीश तिवारी, श्री आनंद भदौरिया, श्री नीरज मौर्य और डॉ. संजय जायसवाल की कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

... (व्यवधान)

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

1201 बजे

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर 2, श्री राव इन्द्रजीत सिंह जी।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION; MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (RAO INDERJIT SINGH): Hon. Speaker Sir, I rise to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Statistical Institute, Kolkata, for the year 2024-2025.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Statistical Institute, Kolkata, for the year 2024-2025, together with Audit Report thereon.

(iii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Statistical Institute, Kolkata, for the year 2024-2025.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY; MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES; MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE; MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS; MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY; AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): Hon. Speaker Sir, with your kind permission, I rise to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Centre for Earth Science Studies, Thiruvananthapuram, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Centre for Earth Science Studies, Thiruvananthapuram, for the year 2024-2025.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the ESSO-NCCOR National Centre for Polar and Ocean Research, Goa, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the ESSO-NCCOR-National Centre for Polar and Ocean Research, Goa, for the year 2024-2025.

(3) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Information Commission, New Delhi, for the year 2024-2025 under sub-section (4) of Section 25 of the Right to Information Act, 2005.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI JITIN PRASADA): Hon. Speaker Sir, with your permission, I rise to lay on the Table:-

(1) A copy of the Aadhaar (Authentication and Offline Verification) Amendment Regulations, 2025 (Hindi and English versions) published in Notification No. F.No. HQ-30011/5/2025-AU-HO in Gazette of India dated 9th December, 2025 under Section 55 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016.

(2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the Digital India Corporation, New Delhi, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the Digital India Corporation, New Delhi, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

1202 बजे

(इस समय श्री इमरान मसूद, श्रीमती शताब्दी राय बनर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

…(व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): I rise to lay on the Table a copy of the Output Outcome Monitoring Framework (Hindi and English versions) of the Ministry of New and Renewable Energy for the year 2026-2027.

——

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (DR. CHANDRA SEKHAR PEMMASANI): Hon. Speaker Sir, with your kind permission I rise to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-
    (i) Review by the Government of the working of the Bharat Broadband Network Limited, New Delhi, for the year 2024-2025.
    (ii) Annual Report of the Bharat Broadband Network Limited, New Delhi, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 14 of the Post Office Act, 2023:-
    (i) The Post Office (Sixth Amendment) Regulations, 2025 published in Notification No. S.O. 6099(E) in Gazette of India dated 30th December, 2025.
    (ii) The Post Office (Seventh Amendment) Regulations, 2025 published in Notification No. S.O. 6154(E) in Gazette of India dated 31st December, 2025.

(4) A copy of the Telecom Commercial Communications Customer Preference (Second Amendment) Regulations, 2025 (Hindi and English versions) published in Notification No. RG-25/(25)/2023-QoS in Gazette of India dated 12th February, 2025 under Section 37 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997.

(5) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.

——

… (*Interruptions*)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल रखता हूं :-

(1) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

… (व्यवधान)

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश चंद्र दुबे) : अध्यक्ष महोदय, मैं खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) का.आ. 5446 (अ) जो दिनांक 26 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित प्राइवेट इकाइयों को कोयला और लिग्नाइट की खोज के लिए पूर्वेक्षण संक्रियाओं को करने के लिए अधिसूचना के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट भारतीय गुणवत्ता परिषद - राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रत्यायित, अधिसूचित प्रत्यायित पूर्वेक्षण अभिकरणों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(2) कोलियरी नियंत्रण (संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.917(अ) में प्रकाशित हुए थे।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI RAVNEET SINGH): Respected Speaker Sir, with your kind permission, I rise to lay on the Table:

(1) A copy of the Report (Hindi and English versions) on the progress made in the intake of Scheduled Castes and Scheduled Tribes against vacancies reserved for them in recruitment and promotion categories on the Railways for the year ending 31st March, 2024.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Article 309 of the Constitution: -

   (i) The Railway Services (Payment of Gratuity under National Pension System) Rules, 2025 published in Notification No. G.S.R. 852(E) dated in Gazette of India dated 17th November, 2025.

   (ii) The Railway Services (Pension) Rules, 2026 published in Notification No. G.S.R. 23(E) dated in Gazette of India dated 13th January, 2026.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No (i) of (3) above.

(5) A copy of the Railway Passenger (Cancellation of Ticket and Refund of Fare) Amendment Rules, 2026 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 41(E) dated in Gazette of India dated 16th January, 2026 under Section 199 of the Railways Act, 1989.

——

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING (SHRI GEORGE KURIAN): Speaker Sir, with your permission, I rise to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the National Minorities Development and Finance Corporation, Delhi, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the National Minorities Development and Finance Corporation, Delhi, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) (i) A copy of the Administrative Report (Hindi and English versions) of the Haj Committee of India, Mumbai, for the year 2023-2024.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Haj Committee of India, Mumbai for the year 2023-2024, together with Audit Report thereon.

(iii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Haj Committee of India, Mumbai, for the year 2023-2024.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

… (*Interruptions*)

लोक लेखा समिति

36वां से 38वां प्रतिवेदन

श्री जय प्रकाश (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मैं लोक लेखा समिति (2025-26) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :-

(1) 'भारतीय रेल में रेलगाड़ी परिचालन में समय की पाबंदी और यात्रा समय' विषय के बारे में लोक लेखा समिति (2025-2026) का छत्तीसवां प्रतिवेदन।

(2) 'ओवरसीज सिटीज़नशिप ऑफ़ इंडिया कार्ड स्कीम के लिए फीस तय करने में गलत विनिमय दर लागू करने के कारण फीस का कम संग्रहण तथा वाशिंगटन और पेरिस स्थित भारतीय मिशनों द्वारा भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना में अनियमितताएं' विषय के बारे में लोक लेखा समिति (2025-2026) का सैंत्तीसवां प्रतिवेदन।

(3) 'कृषि फसल बीमा योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा' के बारे में लोक लेखा समिति के अठहत्तरवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी अड़तीसवां प्रतिवेदन ।

भारत और अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के बारे में वक्तव्य

1204 बजे

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इस सदन के माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की फरवरी, 2025 में अमेरिका यात्रा के बाद से, भारत और अमेरिका एक संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते को संपन्न करने के उद्देश्य से नियमित रूप से चर्चा करते रहे हैं। ... (व्यवधान)

इसी को ध्यान में रखते हुए, दोनों पक्षों के वार्ताकारों ने पिछले एक वर्ष में विभिन्न स्तरों पर गहन बातचीत की है। दोनों पक्षों के महत्वपूर्ण और विविध हितों को देखते हुए, यह स्वाभाविक है कि दोनों पक्ष अपनी-अपनी अर्थव्यवस्थाओं के महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करते हुए सर्वोत्तम संभव परिणाम सुनिश्चित करना चाहेंगे। ... (व्यवधान)

(1205/MK/SMN)

इन वार्ताओं के दौरान भारतीय पक्ष अपने संवेदनशील क्षेत्रों, विशेषकर कृषि और दुग्ध क्षेत्रों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है। ... (व्यवधान) अमेरिकी पक्ष के भी कुछ ऐसे क्षेत्र थे, जो उनके दृष्टिकोण से संवेदनशील थे। लगभग एक वर्ष तक चले कई दौर के विचार-विमर्श के बाद दोनों वार्ताकार दल द्विपक्षीय व्यापार समझौते के कई क्षेत्रों को अंतिम रूप देने में सफल रहे। 2 फरवरी, 2026 को प्रधानमंत्री जी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर फोन पर चर्चा की। ... (व्यवधान) उसके बाद राष्ट्रपति ट्रम्प ने अमेरिका को किए जाने वाले भारतीय निर्यात की दर घटाकर 18 प्रतिशत करने की घोषणा की।

मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यह अमेरिका द्वारा कई प्रतिस्पर्धी देशों पर लगाए गए टैरिफ से कम है, जिससे अमेरिकी बाजार में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी।... (व्यवधान) यह समझौता भारतीय निर्यातकों को विशेष रूप से श्रम प्रधान क्षेत्रों और विनिर्माण में महत्वपूर्ण तुलनात्मक लाभ भी प्रदान करता है। मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष यह दोहराना चाहता हूं कि खाद्य और कृषि क्षेत्र में भारत की प्रमुख संवेदनशीलता का पूर्णत: ध्यान रखा गया है।

साथ ही, यह साझेदारी लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमईज), उद्यमियों, कुशल श्रमिकों और उद्योग के लिए नए अवसर खोलेगी। ... (व्यवधान) उन्नत प्रौद्योगिकियों तक पहुंच को सुगम बनाएगी और भारत के मेक-इन-इंडिया फॉर द वर्ल्ड, डिजाइन-इन-इंडिया फॉर द वर्ल्ड और इनोवेट-इन-इंडिया फॉर द वर्ल्ड के दृष्टिकोण को साकार करने में सहायक होगी।... (व्यवधान)

यह ऐतिहासिक ढांचागत समझौता भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूत करने और 'विकसित भारत-2047' की दिशा में हमारी यात्रा को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच मजबूत जुड़ाव को भी दर्शाता है, जो स्वाभाविक साझेदार हैं और साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि आगे की कार्रवाई के संदर्भ में दोनों पक्ष व्यापार समझौते से संबंधित आवश्यक तकनीकी प्रक्रियाओं को पूरा करने और कागजी कार्रवाई को अंतिम रूप देने के लिए मिलकर काम करेंगे, ताकि इसकी पूरी क्षमता का शीघ्रता से लाभ उठाया जा सके। ... (व्यवधान) समझौते की विस्तृत रूपरेखा इन प्रक्रियाओं के समापन के पश्चात तुरंत घोषित की जाएगी। माननीय सदस्यों को भारत के ऊर्जा स्त्रोतों से संबंधित उन मुद्दों की जानकारी होगी, जो इस समझौते पर हुई चर्चाओं के दौरान उठाये गए हैं।

मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जैसा कि सरकार ने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा आवश्यकताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोत्तम प्राथमिकता है।... (व्यवधान)

(1210/ALK/RP)

वस्तुनिष्ठ बाजार स्थितियों और बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों के अनुरूप ऊर्जा स्त्रोतों में विविधता लाना हमारी इस कार्यनीति का मूल आधार है।... (व्यवधान) भारत की सभी कार्रवाइयां इसी बात को ध्यान में रखकर की जाती हैं।... (व्यवधान)

अतः मैं माननीय सदस्यों से इन मुद्दों को समुचित दृष्टिकोण से देखने का आग्रह करता हूं।... (व्यवधान) दोनों देशों के बीच भावी व्यापार अवसरों के संदर्भ में माननीय सदस्यगण इस बात को समझेंगे कि भारत और अमेरिका काफी हद तक एक दूसरे की पूरक अर्थव्यवस्थाएं हैं।... (व्यवधान)

जैसे-जैसे भारत विकसित भारत के पथ पर अग्रसर हो रहा है, हमें ऊर्जा, विमानन, डेटा केंद्र और परमाणु ऊर्जा आदि सहित कई क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता होगी। … (व्यवधान) अमेरिका इन क्षेत्रों में दुनिया का अग्रणी देश है, इसलिए हमारे लिए इन क्षेत्रों में व्यापार की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना स्वाभाविक है, जिससे न केवल हमारी खरीद में, बल्कि हमारे अपने निर्यात में भी विस्तार होगा।… (व्यवधान)

हमारा अनुमान है कि तुलनात्मक लाभ के परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में भारत का निर्यात अमेरिका में भी काफी बढ़ेगा।… (व्यवधान) विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ यह ढांचागत समझौता, जो आने वाले वर्षों में वैश्विक विकास और नवाचार को गति प्रदान करेगा।… (व्यवधान) यह समझौता भारत की जनता और राष्ट्र के व्यापक हित में है और देश को बहुत लाभ देगा।… (व्यवधान) यह विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत दोनों को सशक्त बनाता है।… (व्यवधान) हम अपने देश के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी के इस दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य करते रहेंगे।

धन्यवाद महोदय। (इति)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यह सदन देश के लोकतंत्र का उच्च सदन है। आप सभी दल समय-समय पर इस देश के अंदर अलग-अलग कालखंड के अंदर सरकार में भी रहे। मेरा मत है कि इतने लम्बे समय तक सरकार में रहने के बाद भी हम इस सदन की मर्यादाओं और परंपराओं को तोड़ रहे हैं। विरोध का तरीका होता है, विरोध के तरीके और भी हो सकते हैं, लेकिन आप अपने स्थान को छोड़कर इस जगह आकर मर्यादाओं को तोड़ेंगे, तो देश के अंदर लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास और भरोसा कम होगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सब चुनकर आते हैं। सदन के अंदर और सदन के बाहर विरोध का तरीका होता है। आप इतने वरिष्ठ नेता हैं। आपने शासन किया है, लेकिन 'नहीं बोलने देना या बोलने देना' यह नियम-प्रक्रिया से चलता है। आप मर्यादा को तोड़ेंगे, क्या यह उचित है? आपके सदस्य इधर से उधर जाएंगे, क्या यह उचित है? क्या आप यही मर्यादा बनाना चाहते हैं? इतने साल शासन करने के बाद क्या आपने यही परम्पराएं लागू की हैं? आप वरिष्ठ लोग हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बालू जी, आप इतने सीनियर नेता हैं। क्या यह आपको अच्छा लग रहा है? मंत्री जी बोल रहे हैं, लेकिन माननीय सदस्य आसन पर जाकर खड़े हो रहे हैं, सत्तापक्ष की तरफ बैनर लेकर आ रहे हैं। मर्यादा में रहकर पहले भी विरोध हुआ है, लेकिन कभी किसी ने मर्यादा नहीं तोड़ी।

… (व्यवधान)

(1215/CP/VPN)

माननीय अध्यक्ष : आप शासन में रहे या प्रतिपक्ष में रहे, तब भी विरोध हुआ, लेकिन मर्यादायें कभी नहीं तोड़ीं। आप जो मर्यादायें तोड़ रहे हैं, यह उचित नहीं है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप शासन को मजबूर नहीं कर सकते हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपसे पुन: आग्रह करता हूं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप मर्यादा रखें, अच्छी परम्परायें रखें। आपका विरोध का तरीका हो सकता है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : विरोध आवाज से नहीं शब्दों से होता है। विरोध तर्कों से होता है। नारेबाजी से, बैनर से विरोध नहीं होता है। विरोध शब्दों और तर्कों से होता है। असहमति मुद्दों पर होती है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वैचारिक मतभेद हैं, तो वैचारिक मतभेद पर बोलना चाहिए। यह सदन वैचारिक मतभेदों पर बोलने के लिए है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या यह तरीका ठीक है?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अगर आप यही तरीका अपनाना चाहते हैं तो अपनायें। मेरा अध्यक्ष के नाते आपसे आग्रह रहता है, सदन से आग्रह रहता है कि सत्ता पक्ष हो या चाहे प्रतिपक्ष हो, सदन की मर्यादाओं, परम्पराओं को बनाकर रखें।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह सभागृह आपका है। आप इस सभागृह का जितना अपमान करेंगे, उतना देश आपको देखेगा। आप इस सभागृह की प्रतिष्ठा को गिराने का कृत्य कर रहे हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इस व्यवस्था के अन्दर सदन चलाना उचित नहीं है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं सदन की कार्यवाही आज दो बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

… (व्यवधान)

1217 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा चौदह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1400/VVK/UB)
1400 बजे

लोक सभा चौदह बजे पुनः समवेत् हुई।

(श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी पीठासीन हुए)

नियम 377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गए

1400 बजे

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, आज जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति दी गई है, वे 20 मिनट के भीतर मामले के पाठ को व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।

Re: Need to attract more Foreign Direct Investment (FDI) to support the tariff affected sectors in the country

SHRI MUKESHKUMAR CHANDRAKAANT DALAL (SURAT): India is facing today one of the highest tariffs of 50% imposed by USA. Exports going to the USA that are targeted the 50% tariff fortunately consists of only 1.21 % of India's GDP services exports are exempted. Thanks to historical GST concessions, there is very robust demand in the economy boosting more private & public sector investments. It is also good to engaged in negotiations with USA to develop some level of understanding to bring some of these tariffs down in some sectors or at least avoid the risk of further escalation. We need to induce those generation of reforms which enhances capabilities of Indian trade & industry which in turn will enhance India's export competitiveness. We need to relook into the import duties on imported inputs which are used in the export goods or items more particularly with reference to goods on which 50% tariffs are imposed which could further increase India's export capabilities & competitiveness. India should take initiatives to attract more FDI, which is showing sign of slowdown due to strong dollar, particularly in tariff affected sectors. I demand that it will be more appropriate to give temporary support to tariff affected sectors like diamond, textile, steel, aluminium, auto etc. In whatever way government could do to further prevent unemployment.

(ends)

Re: Need to establish a CSD Canteen in Sabarkantha Parliamentary Constituency

श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया (साबरकांठा) : मेरे लोकसभा क्षेत्र साबरकांठा (गुजरात) के साबरकांठा व अरावली जिले में लगभग 25,000 सेवानिवृत्त सैनिक एवं पूर्व सैनिक परिवार निवास करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा इन परिवारों को दैनिक उपयोग की वस्तुएँ सैनिक कैंटीनों के माध्यम से रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाती हैं। किन्तु वर्तमान में साबरकांठा क्षेत्र के पूर्व सैनिकों हेतु निकटतम सैनिक कैंटीन गांधीनगर में स्थित है। दूरस्थ ग्रामीण एवं आदिवासी बहुल क्षेत्रों से आने वाले पूर्व सैनिकों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके कारण उन्हें अत्यधिक यात्रा व्यय वहन करना पड़ता है। अतः, मैं अनुरोध करती हूँ कि— मेरे लोकसभा क्षेत्र साबरकांठा के हिम्मतनगर या अरावली जिले के किसी उपयुक्त नगर में एक स्थायी सैनिक कैंटीन (CSD Canteen) की स्थापना की जाए। इससे इस क्षेत्र जोकि राजस्थान से सटा हुआ पर्वतीय क्षेत्र है, के सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी, वीरांगनाएँ तथा उनके परिवारजन सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ अपने ही नजदीकी क्षेत्र में सहज रूप से प्राप्त कर सकेंगे। माननीय मंत्री जी द्वारा इस विषय पर यथोचित कार्रवाई की जाए तो मैं आपकी तथा इस सदन की अत्यंत आभारी रहूँगी।

(इति)

Re: Need to erect a memorial in honour of Shaheed Madho Singh, a revered freedom fighter of Ghess movement in Bargarh, Odisha

श्री प्रदीप पुरोहित (बारगढ़) : मैं इस सदन का ध्यान ओडिशा के बरगढ़ ज़िले की ऐतिहासिक वीरभूमि घेस तथा 1857 के महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद माधोसिंह और उनके परिवार के अभूतपूर्व बलिदान की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। घेस के आदिवासी ज़मींदार माधोसिंह ने 71 वर्ष की आयु में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया। मात्र 356 रुपये वार्षिक लगान देकर वे शांत जीवन जी सकते थे,किंतु स्वाभिमान और देशभक्ति के कारण उन्होंने संघर्ष का मार्ग चुना। उनके चारों पुत्र—हाते,कुंजल,बैरी और ऐरी—भी इस आंदोलन में सहभागी बने। 19 जनवरी 1858 को सिंहोडाघाट सहित कई युद्धों में घेस की सेना ने अंग्रेज़ों को कड़ी चुनौती दी। 31 दिसंबर 1858 को माधोसिंह को संबलपुर में फाँसी दी गई। इसके बाद उनके पुत्रों ने 1864 तक संघर्ष जारी रखा—हाते सिंह को कालापानी भेजा गया, कुंजल सिंह को फाँसी दी गई, बैरी सिंह की आजीवन कारावास में मृत्यु हुई और ऐरी सिंह को अमानवीय ढंग से मार दिया गया। एक ही परिवार के पाँच सदस्यों का यह बलिदान अत्यंत दुर्लभ है। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि शहीद माधोसिंह और घेस विद्रोह पर प्रामाणिक शोध कराया जाए, उनकी स्मृति में राष्ट्रीय स्मारक बने तथा किसी राष्ट्रीय योजना/संस्थान का नाम उनके नाम पर रखा जाए।

(इति)

Re: Need to install statue of Bharat Ratna and former Prime Minister Late Shri Atal Bihari Vajpayee in Sandila, Hardoi district, Uttar Pradesh

श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख) : मैं केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि भारत रत्न जनप्रिय लोकप्रिय पूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई जी का मेरे संसदीय क्षेत्र मिश्रिख के कस्बा संडीला से गहरा जुड़ाव रहा है। वे संडीला के कार्यक्रमों में आते थे। 1945 में जब वह कानपुर के डीएवी कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे इस दौरान वह संघ के कार्य से संडीला आए और करीब दो माह का समय संडीला को समर्पित किया। अटल जी ने वहां कई बार पैदल ही पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया है मैं जब-जब क्षेत्र भ्रमण करने जनता की समस्याओं को जानने और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा किए गए जनहित कार्यों को लोगों तक पहुंचाने के लिए जाता हूं तब तक स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई जी की संडीला तहसील में अथवा इंडस्ट्रियल एरिया में मूर्ति स्थापित किए जाने की मांग की जाती रही है। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि जनमानस की भावनाओं को देखते हुए भारत रत्न जनप्रिय लोकप्रिय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई जी की संडीला जनपद हरदोई उत्तर प्रदेश में मूर्ति स्थापित करने हेतु संबंधित को आदेशित करने की कृपा करें।

(इति)

Re: Need to construct a Railway Overbridge at Baihar railway crossing (JJ-37) in Balaghat, Madhya Pradesh

श्रीमती भारती पारधी (बालाघाट) : मैं सदन का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र बालाघाट की एक अत्यंत गंभीर एवं जनहित से जुड़ी यातायात समस्या की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। बालाघाट नगर में स्थित बैहर रेलवे क्रॉसिंग (जेजे-37) नगर के प्रमुख मार्गों में से एक है। इस रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेनों की अत्यधिक आवाजाही के कारण दिन में कई बार फाटक बंद रहता है, जिससे दोनों ओर घंटों लंबा जाम लग जाता है। इस जाम का सीधा प्रभाव आम नागरिकों, व्यापारियों, विद्यार्थियों, महिलाओं और बुजुर्गों पर पड़ता है। कई अवसरों पर एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन एवं अन्य आपातकालीन सेवाएँ समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुँच पातीं, जिससे जनजीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। लगातार बढ़ते यातायात दबाव और जनसुरक्षा की दृष्टि से बैहर रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण अब समय की अनिवार्य आवश्यकता बन चुका है। इस ओवर ब्रिज के निर्माण से न केवल यातायात सुचारु होगा, बल्कि दुर्घटनाओं में कमी आएगी और क्षेत्र की सुरक्षा भी सुदृढ़ होगी। अतः मैं केंद्र सरकार से आग्रह करती हूँ कि जनसुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए बैहर रेलवे क्रॉसिंग (जेजे-37) पर रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण हेतु शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाए तथा आवश्यक बजटीय प्रावधान सुनिश्चित किया जाए।

(इति)

Re: Need to restore the Old Pension Scheme for eligible employees of Swami Vivekanand National Institute of Rehabilitation Training and Research (SVNIRTAR), Cuttack, Odisha

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): I wish to draw the kind attention of the Ministry of Social Justice and Empowerment to the issue of discontinuation of the Old Pension Scheme (OPS) for eligible employees of Swami Vivekanand National Institute of Rehabilitation Training and Research (SVNIRTAR), Cuttack, an autonomous body under the administrative control of the Ministry. SVNIRTAR employees have historically enjoyed pensionary benefits at par with Central Government employees, including GPF-cum-Pension, as provided under its Bye-Laws. At present, 235 retired employees are receiving pensions under Central Government rules. However, due to recent directives issued by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities in November 2024, the Institute has been instructed to stop issuing fresh Pension Payment Orders, affecting 59 employees who were recruited prior to 1 January 2004 and are otherwise fully eligible for OPS. It is pertinent to mention that the Department of Expenditure, in its letter dated 26 December 2024, has clarified the applicability of OPS to regular employees of National Institutes and Composite Regional Centres (CRCs) recruited before the cut-off date. Moreover, several similarly placed autonomous bodies under other Ministries continue to follow OPS. I, therefore, urge upon the Government to intervene and restore the Old Pension Scheme for eligible employees of SVNIRTAR, ensuring fairness, parity, and protection of their legitimate pensionary rights.

(ends)

Re: Construction of a bridge on NH 55 at Gudia Kateni in Dhenkanal Parliamentary Constituency

श्री रुद्र नारायण पाणी (धेन्कानल) : ओडिशा के कटक-संबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम संख्या 55 स्थित गुडिआ-कटेणी छक से हिंदोल को रास्ता गया है। विपरीत दिशा में बहुत सारे गांव हैं एवं यह मार्ग शरणश्री क्षेत्र की ओर जाता है। अतः इस छक में आजकल अत्यधिक यातायात हो रहा है। दुर्घटना में जानमाल का नुकसान हो रहा है। वहाँ पर एक ओवरब्रिज बनाए जाने की नितांत आवश्यकता है। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि इस दृष्टि से अविलंब हस्तक्षेप किया जाए। अंगुल जिले के गोड़ीबंध छक (चौक) से एन.टी.पी.सी. छक तक की मार्ग के मालिकाना हक को लेकर जो विवाद है उसका तुरंत समाधान किया जाए। यह खंड राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम संख्या 53 का अंश विशेष है। पहले इस राजमार्ग की संख्या 200 थी। एन.टी.पी.सी. के स्थानीय इकाई टी. एस. टी. पी. पी. इस पर अपना हक जताता है लेकिन जो भी हो यात्रियों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। एन.एच.ए.आई. को यह भूमि तुरंत मिल जानी चाहिए एवं जल्द से जल्द विकसित मार्ग बनाया जाए।

(इति)

Re: Development of Satna to Chitrakoot path as a Rampath Gaman Marg under Ramayan Circuit in Madhya Pradesh

श्री गणेश सिंह (सतना) : मेरे लोकसभा क्षेत्र सतना और उससे लगा हुआ चित्रकूट धाम केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि भारत की आत्मा, संस्कृति और सनातन परंपरा का केंद्र है। यही वह पुण्यभूमि है जहाँ भगवान श्रीराम ने अपने वनवास के साढ़े ग्यारह वर्ष बिताए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा वर्णित चित्रकूट, आज भी रामकथा की जीवंत साक्षी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में देश-भर में रामायण सर्किट की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। अयोध्या का भव्य विकास, स्वरूपण और वैश्विक पहचान इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निम्नलिखित जानकारी चाहता हूं – (1) सतना से चित्रकूट होते हुए रामायण सर्किट को जोड़ने के “रामपथ गमन” प्रस्ताव पर अब तक संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? (2) क्या मंत्रायल द्वारा चित्रकूट होते हुए 84-कोसी परिक्रमा पथ पर स्थित समस्त तीर्थ स्थलों को रामायण सर्किट से जोड़ने की योजना है? (3) क्या भविष्य में चित्रकूट में एक समर्पित “रामायण संस्थान” की स्थापना पर विचार किया जा रहा है, जिससे शोध, संस्कृति संरक्षण और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल सके? इससे स्थानीय रोजगार, पर्यटन, संस्कृति संरक्षण और क्षेत्रीय विकास को भी नया आयाम मिलेगा।

(इति)

Re: Construction of a railway over bridge on level crossing No. 104 in Pindwara in Sirohi district, Rajasthan and other railway related issues

श्री लुम्बाराम चौधरी (जालौर) : पिण्डवाड़ा सिरोही जिला (राजस्थान) की आम जनता को हो रही कठिनाईयों के मद्देनजर रेलवे बोर्ड ने अपने 23 दिसम्बर, 2023 के आदेश संख्या 2022/CE-IV/PH30/Umb.22-23/NWR-124 के द्वारा महाप्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे को पिंडवाड़ा में रेल लाइन पर बंद पड़े रेल फाटक / लेवल क्रासिंग संख्या 104 किमी 555/4 पर ₹ 5.68 करोड़ की लागत पर रेल्वे अंडर पास (RUB) के निर्माण कार्य किए जाने की स्वीकृती प्रदान की थी। अत इसका निमार्ण जल्द से जल्द किया जाए। करोना काल के पूर्व जयपुर से अहमदाबाद चलने वाली लोकल 54805 अप और 54806 डाउन ट्रेन को पुनः शुरू करने अथवा 19735 अप और 19736 डाउन जयपुर से मारवाड को अहमदाबाद तक विस्तार किया जाए। बाकरा रोड तथा मारवाड बागरा दोनो रेलवे स्टेशन पर सुपरफास्ट एवं एक्सप्रेस ट्रेनो का ठहराव दिया जाए। MGR Chennai Central - Bhagat ki Kothi SF Express 20625/20626 एक्सप्रेस ट्रेन का मोदरान स्टेशन पर ठहराव दिया जाए। जालोर से जयपुर - दिल्ली वाया लूनी - पाली मारवाड़ (रेलमंत्री की घोषणा अनुसार) नई रेल प्रारंभ किया जाए। जोधपुर से वाया जालोर होकर हैदराबाद, एर्नाकुलम, नागपुर बेल्लारी बैंगलुरु काकीनाडा विशाखापट्टनम रामेश्वरम और पुणे आदि शहरों के लिये नई रेल शुरू किया जाए।

(इति)

Re: Need to upgrade Akola-Nagpur and Akola-Khamgaon stretches of NH-53 to six laning road in Maharashtra

SHRI ANUP SANJAY DHOTRE (AKOLA): I would like to bring to your notice whether the Government is working towards upgrading four-lane highways into six-lane corridors where a minimum traffic volume of 20,000 PCUs is prescribed, and how many National Highway stretches across the country have been identified as eligible under this criterion. Further, I seek to know the major challenges being faced in implementing such projects, including land acquisition, environmental clearances, funding, and execution. I would also like to ask whether, if only a part of a highway stretch qualifies for upgradation — especially high-density traffic sections near urban centres such as Nagpur — the Government undertakes partial six-laning of such stretches. Lastly, I request the Hon'ble Minister to clarify whether the Akola–Nagpur and Akola–Khamgaon stretches of NH-53, particularly the sections near Nagpur (Gondkhairi Toll Plaza) on Nagpur Kondhali Section of NH 53, satisfy the prescribed PCU criteria for six-laning, and to provide the present status and likely timeline for their upgradation.

(ends)

Re: Infiltration of Bangladeshi nationals in Assam and their repatriation to their home country

श्री दिलीप शइकीया (दारंग-उदालगुड़ी) : असम में बांग्लादेशी अवैध घुसपैठ का मुद्दा राज्य की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। 1971 में बांग्लादेश के अलग देश बनने से पहले और उसके बाद भारी संख्या में लोग असम में आकर बसने लगे थे। बांग्लादेश से असम में अवैध प्रवास असमिया लोगों की पहचान के लिए एक गंभीर सुरक्षा खतरा बन गया है। यह असम के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और कानून-व्यवस्था की समस्याएँ भी पैदा करता है। इससे यहाँ की जनसांख्यिकी में भी भारी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। 1951-2011 की अवधि में असम राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर 288.21% रही, जबकि पूरे भारत में यह 235.15% थी। यह उच्च वृद्धि दर स्पष्ट रूप से असम राज्य में बड़े पैमाने पर प्रवासन का संकेत देती है। असम समेत पूर्वोत्तर भारत में अवैध घुसपैठ को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच कोई समझौता नहीं होने के कारण, बांग्लादेश द्वारा अपने इन अवैध घुसपैठियों को वापिस नहीं लिया जाता है , जोकि देश की सुरक्षा के लिए एक गंभीर संकट है। केंद्र सरकार से अनुरोध है कि बांग्लादेश के साथ अवैध घुसपैठ को लेकर द्विपक्षीय समझौता किया जाए और बांग्लादेश से आये घुसपैठियों को वापिस भेजा जाए।

(इति)

Re: Need to establish an extension counter of CSD/ESM canteen in Nalagarh, Solan district in Himachal Pradesh

श्री सुरेश कुमार कश्यप (शिमला) : मैं सरकार का ध्यान अपनी लोकसभा क्षेत्र शिमला के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन स्थित नालागढ़ क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जहाँ सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों की बड़ी संख्या निवास करती है। नालागढ़ तथा इसके आसपास के औद्योगिक क्षेत्र में सेवारत सैनिक परिवारों एवं पूर्व सैनिकों को CSD कैंटीन की सुविधाओं के लिए वर्तमान में दूरस्थ स्थानों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे उन्हें अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 16 जनवरी 2025 को नालागढ़ में ESM/CSD कैंटीन एक्सटेंशन काउंटर की स्थापना हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। इस प्रस्ताव पर HQ Army Training Command, शिमला द्वारा भी परीक्षण किया गया है, जिसमें नालागढ़ क्षेत्र में एक्सटेंशन काउंटर की आवश्यकता को वास्तविक एवं जनहित में माना गया है। अतः मैं माननीय रक्षा मंत्री से आग्रह करता हूँ कि सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों की सुविधा एवं कल्याण को ध्यान में रखते हुए नालागढ़, जिला सोलन (लोकसभा क्षेत्र शिमला) में शीघ्र CSD/ESM कैंटीन एक्सटेंशन काउंटर की स्थापना हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने की कृपा करें।

(इति)

Re: Need for mandatory scrutiny of court cases where judgments are against the Government policies

श्री अतुल गर्ग (गाजियाबाद) : पूरे देश में शासन-प्रशासन बनाम आम नागरिकों/व्यवसायियों के बीच लाखों मामले विभिन्न मंचों पर लंबित हैं। वर्षों तक मुकदमेबाज़ी चलने के बाद जब निर्णय आते हैं, इन मामलों में से लगभग आधे या उससे अधिक मामलों के निर्णय सरकार के विरुद्ध आते हैं। तो यह आवश्यक है कि इन मामलों की समीक्षा अनिवार्य रूप से की जाए। अनेक मामलों में सरकारी अधिकारियों द्वारा निर्णय न लेना, गलतफ़हमी में निर्णय लेना, लापरवाही से निर्णय लेना, जानबूझकर गलत निर्णय लेकर नागरिकों को प्रताड़ित करना, बिना कारण आपत्तियाँ लगाना, बार-बार अनावश्यक स्पष्टीकरण माँगना। ऐसी प्रक्रियाओं के कारण न सिर्फ नागरिकों का समय व धन नष्ट होता है, बल्कि सरकार को भी अनावश्यक मुकदमों में पराजय एवं वित्तीय हानि उठानी पड़ती है। अतः सुझाव है कि पीड़ित पक्ष की शिकायत को प्राथमिकता देते हुए कम से कम 5% से 10% मामलों की अनिवार्य स्क्रूटनी /ऑडिट की जाए, जिनमें सरकार के विरुद्ध निर्णय आए हों। अंततः यह प्रक्रिया सरकार और जनता दोनों के हित में होगी तथा मुकदमेबाज़ी का बोझ कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। (इति)

Re: Need to provide adequate number of rehabilitation centres alongwith financial assistance to support Autism Spectrum Disorder (ASD) patients and other Divyangjan in country

SHRI SHAFI PARAMBIL (VADAKARA): There is an alarming increase in the number of parents who commit suicide after killing their intellectually challenged child. Twenty differently-abled people have been killed by their parents in Kerala in the last two years. All twenty tragic events mentioned above occurred out of a deep sense of frustration and social exclusion that they had to suffer due to the disability of their children. Children and adults suffering from intellectual disability require lifelong support and care, as they are unable to distinguish between food and excrement. Naturally, caring for a disabled child leads to high levels of stress, tension, and financial burden to the parents. As of now, the early intervention centres and rehabilitation centres for children suffering from ASD are inadequate in comparison with the number of ASD patients. There is a direct correlation between the homicide of ASD children with ASD and the depression of parents. The existing social security schemes cannot address the fundamental issues faced by these people. They need wholehearted support from the government, society, and institutions. Therefore, there is an urgent need to intervene and support disabled people with more rehabilitation centres, care homes, and financial support for their treatment and medicine.

(ends)

Re: Need to improve Aadhaar Update Services in Rajasthan

श्री उम्मेदा राम बेनीवाल (बाड़मेर) : मैं नियम 377 के अंतर्गत राजस्थान में आधार सुधार सेवाओं में व्याप्त गंभीर खामियों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जन्मतिथि एवं लिंग से संबंधित आधार सुधार की समस्याएँ स्थानीय स्तर पर हल नहीं हो पा रही हैं, जिससे नागरिकों को दिल्ली तक अना पड़ रहा है, जिससे समय और धन दोनों की हानि हो रही है। यह भी सामने आया है कि आधार में सुधार के लिए केवल दो बार अवसर दिया जाता है और दिल्ली में प्रतिदिन लगभग 220 टोकन ही जारी किए जाते हैं आधार में सुधार के लिए। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा टोकनों की कालाबाज़ारी कर उन्हें ₹5,000–₹6,000 में बेचने की गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सुबह 6 बजे टोकन वितरण की व्यवस्था से बुज़ुर्गों, महिलाओं और गरीब वर्ग को भारी कठिनाई होती है। राज्य स्तर पर प्रभावी व्यवस्था न होने के कारण दिल्ली में एक ही बेंच कई राज्यों के मामलों को देख रही है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि राज्य स्तर पर सुधार सुविधाएँ सुदृढ़ की जाएँ, कालाबाज़ारी पर कठोर कार्रवाई हो तथा निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।

(इति)

Re: Need for a special recruitment drive for Nagaland Doordarshan Kendra and All India Radio, Kohima with relaxation of Hindi language proficiency test

SHRI S. SUPONGMEREN JAMIR (NAGALAND): In 2013 as per the employment news/Rozgar samachar dated 23-03-2013 the Staff Selection Commission (SSC) has advertised the vacant post of [1] Prgramme executive & [2] Transmission for post of transmission Executive (Production Assistant) 15 post for Doordarshan & All India Radio for Nagaland State, but no candidates was qualified from Nagaland as they could not get through in Hindi Paper II subject. The Present sanctioned post for both the stations at Nagaland Doordarshan Kendra, Kohima 1. No of post Sanctioned -144 a. No. of post in position- 55 b. No. of vacant post- 89 [2] All India Radio Kohima a] Total sanction post of Programme Section -79 1] in position-15 2] vacant-64 B} administration staff-90 a] in position-34 c] vacant-56 b] Engineering staff-91 1] in position-41 2] vacant-50 request to hon'ble Minister to consider special recruitment drive for Nagaland state with the relaxation of Hindi and make the paper I & II in English.

(ends)

Re: Need to include OPD services and diagnostics under Ayushman Bharat Scheme (PM-JAY)

SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR): I wish to raise a matter of urgent public importance regarding the expansion of Ayushman Bharat (PM-JAY). The Parliamentary Standing Committee on Health highlights that nearly 70% of health spending in India is on outpatient (OPD) care, which remains excluded from PM-JAY. This financial burden forces the poor into a debt trap, as they must pay for consultations and medicines out-of-pocket. Studies show that high OPD costs discourage people from seeking timely medical help. Consequently, many patients wait until their condition becomes life-threatening before visiting a hospital, leading to preventable deaths and higher costs for the State. I urge the Hon'ble Minister of Health and Family Welfare to include essential OPD services and diagnostics under the scheme to promote early diagnosis and ensure that no family falls into poverty due to routine medical expenses.

(ends)

Re: Need to abolish toll collection charges on NH66-Kozhikode bypass in Kerala

SHRI M. K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): I wish to draw the attention of the Hon'ble Minister of Road Transport and Highways to serious public concerns regarding the commencement of toll collection on the NH-66 Kozhikode Bypass, despite the project remaining incomplete. Major works at critical locations are still pending, while construction continues along several stretches, making the bypass unfit for full operation. Absence of adequate and continuous service roads has severely affected local connectivity, even two-wheelers and three-wheelers are compelled to travel on the main carriageway, causing serious safety concerns. This situation renders toll collection unjustified and is likely to cause congestion and public hardship. Educational institutions have been charged toll on the ground that they are not classified as non-commercial. However, educational institutions, whether Government, aided, unaided or private are not fully commercial in nature and therefore provision for issuing monthly passes to them is necessary. Further, the lack of proper pedestrian pathways along service roads poses serious safety risks, particularly to senior citizens, students and women. Hence, I request urgent intervention of Hon'ble Minister to immediately stop toll collection until the project is completed and adequate service roads and pedestrian facilities are ensured, in the interest of safety and public convenience. (ends)

Re: Need to provide adequate compensation to farmers affected by Montha Cyclone

श्री सनातन पांडेय (बलिया) : मौंथा तुफान से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है एवं रबी की बुआई भी प्रभावित हुई है एवं किसानों को उर्वरक समय पर उपलब्ध हो पाया है। अत: मेरा सरकार से आग्रह है कि इस संबंध मे त्वरित कार्यवाही करते हुए प्रभावित किसानो को मुआवजा देने की व्यवस्था करें।

(इति)

Re: Need to enhance the MSP of Sugarcane and provide good quality seeds, fertilizers and pesticide at affordable price in Uttar Pradesh

श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर (खीरी) : मैं आपका ध्यान अतिमहत्वपूर्ण विषय "उतर प्रदेश के गन्ना किसानों के खराब हालात और परेशानीयों की और आकृष्ट कराना चाहता हूँ। विगत कई वर्षों से गन्ने की खेती में लागत बढ़ती जा रही है। खाद (यूरिया, डीएपी, एनपीके) के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कीटनाशक दवाईयां के दाम भी बढ़तेजा रहे हैं। एक ओर जहाँ सिंचाई मंहगी हो रही है वंही मजदूरों की मजदूरी भी बढ़ रही है। गन्ने की बीज की प्रजातियाँ (जो ज्यादा उपज दे सके) भी किसानों को उपलब्ध नहीं हो रही है, जिससे की गन्ने की उपज कम हो रही है। बढ़ती लागत के हिसाब से गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ रहा है, तथा चीनी मिलें गन्ना किसानों को गन्ने का भुगतान भी समय पर नहीं दे रही है गन्ना किसान सब ओर से मजबूर हो कर भी गन्ने की खेती कर रहे हैं। अतः मैं सरकार से और माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी से जनहित में आग्रह करता हूँ कि गन्ने का मूल्य 400 रु/क्विंटल से बढ़ा कर 500रु / क्विंटल करें, किसानों को ज्यादा उपज दिलाने वाले बीज की प्रजातियाँ उपलब्ध कराएं और किसानों को कम दाम में खाद और कीटनाशक दवाईयां करा कर ना केवल उत्तर प्रदेश के किसानों बल्कि देश के किसानों को कष्ट से उबारने का कार्य करें। (इति)

Re: Need for direct flight connectivity between Kolkata and Jeddah, Saudi Arabia

SHRI YUSUF PATHAN (BAHARAMPUR): A direct flight between Kolkata and Jeddah, Saudi Arabia has been a longstanding demand from the people of West Bengal. There are direct flights from Delhi, Mumbai, Kochi, Ahmedabad, Hyderabad, Bengaluru and Pune to Jeddah. Yet there are no direct flights between Kolkata, the third most populous metropolitan city and Jeddah. With over 26,000 haj pilgrims travelling to Saudi Arabia between 2022 and 2025 from West Bengal and a similarly significant number of Umrah pilgrims, direct flight connectivity becomes particularly important. Currently, flying between Kolkata and Jeddah takes over 10 hours due to layovers. This imposes significant hardships on passengers, in terms of travel time, ticket prices and overall convenience. Establishing direct flight connectivity between Kolkata and Jeddah would ease not just the travel woes of pilgrims, but also that of tourists, expatriates, workers and business travellers. Such direct flight connectivity will also cater to passengers from the broader eastern and north eastern region. Hence, I request the government to take prompt action to establish direct flight connectivity between Kolkata and Jeddah. (ends)

Re: Need to expedite granting the Geographical Indication (GI) tag to Sholapith craft in West Bengal

SHRIMATI JUNE MALIAH (MEDINIPUR): Nearly 377 artisans across 12 districts of West Bengal are engaged in production and trade of Sholapith craft, an industry with an estimated annual turnover of about Rs 6 crore. Although the Government of West Bengal has already submitted an application for a Geographical Indication tag for Sholapith craft in 2022, it remains pending with the Union Government. Even after three years the GI tag has not been granted. Sholapith work is an integral part of Bengal's cultural heritage and identity, closely linked to religious rituals and practices. Even today, no puja is performed without floral decorations for deities or the topar made of Sholapith. The craft is even used for goddess Durga during Durga Puja, marriage and death rituals. Further, it is used in ornaments, toys, decorative articles, and utilitarian items such as packaging and repair materials. Renowned for its elegance, exquisite beauty, and fine craftsmanship, Sholapith craft represents one of Bengal's most distinctive and delicate artistic traditions. The delay in granting the GI tag is extremely concerning, as it deprives artisans of due recognition and protection of their heritage. It further raises serious concerns about the neglect of Bengal's cultural identity.

(ends)

Re: Railway related issues in Tamil Nadu.

SHRI MURASOLI S. (THANJAVUR): The Survey of New Railway Lines from Thanjavur – Pudukkottai, Ariyalur – Thanjavur – Pattukottai, Mannargudi – Pattukottai for Railway Lines were commissioned at the time of the British, more than 90 years back and still hasn't been taken up by the Railway Board. These lines should be prioritized and should be commissioned at the earliest. These Railway lines are crucial to this region and will connect all major railway lines in a circular loop. This will also enable the railways to provide more rail services to this region and to provide freight services to the farmers in the delta region. These railway lines should be commissioned at the earliest to ease the travel of the people of the region. Also, Villupuram – Thanjavur Section of Main Line should be doubled as the line has already attained saturation and is running at more than 100% of track capacity, leading to numerous delays. Hence, the line should be doubled at the earliest for the convenience of the passengers. Moreover, A New Vande Bharat Train from Thanjavur Jn to Mysore should be introduced to connect these two cultural and heritage cities and cater to the increased demand of this rail route.

(ends)

Re: Need to formulate a uniform national policy to safeguard the minor children from social media

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): I rise to highlight the need for a forward-looking national policy on children's access to social media platforms. The rapid and largely unregulated growth of social media has made children a highly vulnerable group online, exposing them to abuse, cyberbullying, and harmful content. Children lack the developmental capacity to navigate these risks safely, yet platforms continue to design systems that draw them in and profit from their attention. While parental controls exist, they are insufficient to address the systemic risks and power asymmetries children face online, highlighting the need for stronger policy intervention. I have also submitted a PMB proposing a minimum age threshold for social media access, robust age-verification norms, and strict deletion of children's data. Globally, Australia has enacted an under-16 ban, while Denmark, Malaysia, Norway, the United Kingdom, and New Zealand are moving towards similar age-based restrictions, signalling a shift in accountability towards platforms. Our NDA-led Government in Andhra Pradesh is examining this issue seriously and exploring the need for a strong legal framework to safeguard young users. I urge the Union Government to also consider a uniform national policy, grounded in child rights and data protection, to ensure a safer digital future for India's children. (ends)

Re: Construction of a bridge over River Kosi in Jhanjharpur Parliamentary Constituency

श्री रामप्रीत मंडल (झंझारपुर) : मेरे संसदीय क्षेत्र झंझारपुर के मधेपुर प्रखंड के भरगामा पंचायत से बकुआ पंचायत के बीच, कोसी नदी प्रवाहित होती है, जिसके कारण लोगों का आवागमन बाधित होता है। यह क्षेत्र काफी पिछड़ा क्षेत्र है, आवागमन की समुचित सुविधा नहीं होने से लोगों की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है। उनकी उपज आदि बाजार तक पहुंचाने में काफी परेशानियां होती हैं। मधेपुर प्रखंड के भरगामा, गढ़गावं, द्वालख, करहारा, बकुआ, कारा, महपतिया, बसीपटी समेत दर्जनों ऐसे गांव हैं जो कोसी नदी के पेट में स्थित है। बरसात में यह इलाका जलमग्न रहता है, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बकुआ ग्राम के निवासी ईंट-खड़ंजे का सपना भी नही देख सकते हैं। इस क्षेत्र के लोगों को आवागमन का कोई रास्ता नहीं है। अतः माननीय सड़क एवं परिवहन मंत्री जी से आग्रह है कि झंझारपुर संसदीय क्षेत्र के मधेपुर ब्लाक के भरगामा पंचायत से बकुआ पंचायत के मध्य कोसी नदी पर RCC पुल का निर्माण कराने की मंजूरी दें, ताकि यह क्षेत्र भी पूर्व-पश्चिम एन एच 27 के कोरीडोर से जुड जाय, इससे दरभंगा आमस एक्सप्रेस-वे का भी जुड़ाव हो जायेगा, इस क्षेत्र को सड़क मार्ग से जुड़ने का अवसर मिलेगा और लोगों का आर्थिक विकास होगा।

(इति)

Re: Alleged irregularities in implementation of Pradhan Mantri Awas Yojana

श्री राजा राम सिंह (काराकाट) : प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है, लेकिन इसका कार्यान्वयन खराब निर्माण, अनियमितता और कागजों पर पूर्ण पर धरातल से गायब घरों जैसी अनियमितताओं से जूझ रहा है। उत्तर प्रदेश पर हालिया सीएजी (CAG) रिपोर्ट ने बुनियादी सुविधाओं के अभाव और अस्तित्वहीन घरों का खुलासा कर सरकारी दावों की पोल खोल दी है। बिहार में बड़ी संख्या में लाभार्थियों को देखते हुए, मैं मंत्री जी से निम्नलिखित विवरण की मांग करता हूँ: क्या पिछले 5 वर्षों में बिहार में PMAY के तहत कोई ऑडिट या निरीक्षण हुआ है? पिछले 5 वर्षों में बिहार से भ्रष्टाचार और फंड न मिलने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं? कितने घर पूर्ण घोषित होने के बावजूद दोषपूर्ण या अस्तित्वहीन पाए गए? फंड के विचलन (diversion) या साइबर धोखाधड़ी के कितने मामले सामने आए और उन पर क्या कार्रवाई हुई? राज्य में जियो-टैगिंग, सोशल ऑडिट और लाभार्थी सत्यापन की वर्तमान स्थिति क्या है? (इति)

Re: Need to implement the policy to give priority in the transfer/posting of women teachers working in KVS near their husband's place of posting

डॉ. राजकुमार सांगवान (बागपत) : मैं सरकार का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। पूर्व में केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) में कार्यरत उन अध्यापिकाओं को, जिनके पति भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना या अर्धसैनिक बलों (CRPF, BSF, ITBP, CISF आदि) में सेवारत हैं, उनके पति के कार्यस्थल के निकट स्थानांतरण में प्राथमिकता दी जाती थी। यह व्यवस्था सैनिक परिवारों के हित में अत्यंत सहायक थी, क्योंकि इससे परिवार एक साथ रह पाते थे और बच्चों की शिक्षा तथा पारिवारिक स्थिरता बनी रहती थी। दुर्भाग्यवश, इस संवेदनशील व्यवस्था को KVS के स्तर पर समाप्त कर दिया गया है। परिणामस्वरूप सैनिकों की पत्नियाँ दूरस्थ स्थानों पर कार्य करने को विवश हैं, जिससे परिवार बिखर रहे हैं। इसका नकारात्मक प्रभाव बच्चों के लालन-पालन, शिक्षा तथा सैनिकों के मनोबल पर स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। अनेक अभ्यावेदन दिए जाने के बावजूद इस विषय पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि सैनिकों एवं अर्धसैनिक बलों के कर्मियों की पत्नियों के लिए पूर्ववर्ती स्थानांतरण प्राथमिकता नीति को शीघ्र पुनः लागू करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए जाएँ। (इति)

Re: Need to upgrade infrastructure, promote cargo, passenger and cruise ship services in Kollam Port in Kerala

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Kollam Port is one of the oldest ports in the country and has an immigration check-post facility, but its infrastructure is inadequate to meet present needs. A coastal shipping project was launched; however, it has not delivered the required outcomes. Several major shipping companies have shown interest in operating from Kollam Port, and it has been established that large foreign vessels can safely operate from this port. Kollam Port is strategically located and is the nearest port to the southern part of Lakshadweep, making it ideal for cargo services to Lakshadweep and Maldives. There is also strong potential for passenger and cruise ship services from Kollam Port. Despite this strategic and commercial potential, the port has not received adequate attention for development. I urge the Government to take immediate steps to upgrade infrastructure, promote cargo, passenger, and cruise ship operations, and fully utilise Kollam Port in a time-bound manner. (ends)

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS -- CONTD.

1401 hours

SHRI G. M. HARISH BALAYOGI (AMALAPURAM): Hon. Chairperson, Sir, I rise on behalf of Telugu Desam Party to extend our support to the gracious Address of the hon. President of India. The Address presents a confident national roadmap rooted in reform, inclusion and long-term competitiveness. The vision of Viksit Bharat 2047 reflects a shift from managing short-term outcomes to shaping enduring economic strength, institutional capacity and global relevance.

1401 बजे

(इस समय डॉ. अमर सिंह, श्री इमरान मसूद, श्रीमती शताब्दी राय बनर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

HON. CHAIRPERSON : Kindly go back to your seats.

… (*Interruptions*)

SHRI G. M. HARISH BALAYOGI (AMALAPURAM): At the centre of this transformation lies technology and digital leadership. The President's Address rightly highlights the creation of over 25 lakh jobs in electronics manufacturing and the engagement of more than one crore young Indians across IT services and Global Capability Centres. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON : Hon. Members, please go back to your seats.

SHRI G. M. HARISH BALAYOGI (AMALAPURAM): Extending tax incentives for data centres and cloud service providers until 2047 sends a strong signal of policy certainty and positions India as a trusted global hub for data, computing and artificial intelligence, while generating high-quality employment. … (*Interruptions*)

Decentralised technology-led growth is now visible on the ground. My State of Andhra Pradesh offers a strong example, with nearly 25 per cent of national investment proposals in 2025-26 flowing into the State, including the proposed 15 billion dollar Google AI hub, the Rs. 798,000 crore Digital Connexion hyperscale campus and the 500 MW FrontierOne data centre. This momentum, driven by focused policy leadership under the hon. IT Minister, Shri Nara Lokesh *garu*, demonstrates what coordinated Centre-State governance and infrastructure readiness can achieve. … (*Interruptions*)

Technology governance must advance in parallel with this growth, with emphasis on regulation and enforcement regarding data privacy, intellectual property and cybercrime to counter modern day misuses of technology such as deepfakes, manipulations and digital addiction especially amongst our youth. … (*Interruptions*) The use of AI in mental healthcare must be strictly regulated, with digital platforms operating under clear standards of privacy protection, ethical design and clinical accountability. … (*Interruptions*)

If technology is the engine of growth, education and skilling are the fuel that powers it. An allocation of Rs. 3,200 crore for Atal Tinkering Labs strengthens innovation, but inclusion must remain central, especially when only 35 per cent of schools in our country currently accommodate children with special needs. … (*Interruptions*) The decision to establish one girls' hostel in every district will expand higher education access, but empowerment must translate into entrepreneurship and economic participation. … (*Interruptions*)

(1405/NKL/SK)

As a panelist at the Viksit Bharat Young Leaders Dialogue, I witnessed strong entrepreneurial aspiration. … (*Interruptions*)

Sir, due to the paucity of time, I would like to conclude. … (*Interruptions*) As I conclude, the President’s Address is a call to national responsibility at a defining moment in India’s journey. … (*Interruptions*) The vision of Viksit Bharat is not confined to one Government or one electoral cycle. … (*Interruptions*) It is a continuous national mission demanding discipline, continuity and collective resolve. … (*Interruptions*)

The Telugu Desam Party, as a part of the NDA Government, stand firmly committed to this mission. … (*Interruptions*) We believe cooperative federalism, policy stability and strong institutions will form the foundation of Viksit Bharat. … (*Interruptions*)

Thank you. … (*Interruptions*)

(ends)

1406 बजे

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : माननीय सभापति जी, धन्यवाद। मैं सर्वानंद सोनोवाल जी और तेजस्वी सूर्या जी द्वारा समर्थित महामहिम राष्ट्रपति अभिभाषण प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। ... (व्यवधान)

सभापति जी, यहां किताब पर चर्चा चल रही है। वह किताब जो आज तक छपी ही नहीं। ... (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार और कांग्रेस परिवार की ... (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) भ्रष्टाचार और ... (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) से भरी पड़ी हैं। ... (व्यवधान) यह छपी हुई किताब है। पहली किताब है - एडविना एंड नेहरू। ... (व्यवधान) भारत जब स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधान मंत्री अय्याशी कर रहे थे, इस किताब में है, मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं।... (व्यवधान) मैं उसे क्वोट करना चाहता हूं। ... (व्यवधान)

दूसरी किताब है, मथाई साहब, जो नेहरू साहब के पीए हुआ करते थे। ... (व्यवधान) वह कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी) : दुबे जी, एक सेकिंड।

... (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में उनको हटाया। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप मेरी बात सुनिए। माननीय अध्यक्ष जी ने रूल 349 में रूलिंग दी है।

... (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : मैं उन किताबों का जिक्र कर रहा हूं। ... (व्यवधान) मैं सारी किताबें लेकर आया हूं।... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप मेरी बात सुनिए।

... (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) और भ्रष्टाचार से कांग्रेस का किया हुआ हाल सारे देश को समझना चाहिए। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: निशिकांत जी, आप मेरी बात सुनिए।

... (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : यह किताब है- द रैड सारी। यह सोनिया जी की किताब है। ... (व्यवधान) किस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार के आधार पर, किस तरह तरह से भ्रष्टाचार के व्यवहार पर इस सरकार को चलाया और दस साल तक किस तरह से करप्शन किया। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप ऐसा नहीं कर सकते।

... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: You please listen to me.

... (*Interruptions*)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : यह इंदिरा जी की किताब है। ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Nishikant Dubey ji, the hon. Speaker has given a ruling yesterday.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: No, I cannot allow this.

... (*Interruptions*)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : जिसमें ... (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) किस तरह के संबंध थे और डिफेंस डीलर्स के क्या संबंध थे।... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: The hon. Speaker has given a ruling yesterday.

... (*Interruptions*)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : यह जनरल थोरट की किताब है कि नेहरू ने चीन को कैसे दे दिया। … (व्यवधान)
माननीय सभापति: दुबे जी, प्लीज़, आप मेरी बात सुनिए।

… (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : यह नेहरू की किताब है कि किस तरह से … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) जो बैन कर दिए गए। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Dubey ji, please listen to me.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The hon. Speaker has given a ruling yesterday that other than the Motion of Thanks on the President's Address, there will be no discussion. So, I cannot allow you.

… (*Interruptions*)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : यह एमरजेंसी की कहानी है। 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' संजय बारू की किताब है। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: No, I cannot allow you.

… (*Interruptions*)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : यह एमरजेंसी रिटोल्ड की कहानी है।… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I cannot allow you to speak on any matter other than the Motion of Thanks on the President's Address.

… (*Interruptions*)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : यह वह कहानी है जिसमें एंडरसन को राजीव गांधी ने बाहर भेज दिया। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Other than the Motion of Thanks on the President's Address, there cannot be any discussion.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please come back on the topic.

… (*Interruptions*)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : यह फली नरिमन की कहानी है कि किस तरह से ज्यूडिशियरी को इन्होंने बर्बाद किया। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: No, you cannot do this.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please come back on the topic of 'Motion of Thanks on the President's Address'.

… (*Interruptions*)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : यह बोफोर्स की कहानी है कि क्वात्रोची से कांग्रेस परिवार के क्या संबंध थे। यह मित्रोखिन लाइब्रेरी है।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सदन की कार्यवाही पांच बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

… (व्यवधान)

1408 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सत्रह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1700/VB/VR)
1700 बजे

लोक सभा सत्रह बजे पुनः समवेत् हुई।
(श्रीमती संध्या राय पीठासीन हुईं)
... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नम्बर 13.
श्री पी. पी. चौधरी जी।

... (व्यवधान)

1701 बजे

(इस समय प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़, श्री शफी परम्बिल, सुश्री एस. जोतिमणि, श्री धर्मेन्द्र यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

... (व्यवधान)

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव – जारी

1701 बजे

श्री पी. पी. चौधरी (पाली) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मौका दिया।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, आप सब अपनी-अपनी सीट पर विराजें।

... (व्यवधान)

श्री पी. पी. चौधरी (पाली) : मैं आपको बताना चाहूंगा कि माननीय स्पीकर महोदय ने बहुत सोच-समझकर एक दलित व्यक्ति को कल सभापतित्व करने का मौका दिया। लेकिन खेद का विषय है कि कांग्रेस पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी के इशारे पर दलित व्यक्ति श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी, जो सभापति की कुर्सी पर बैठे थे, के ऊपर कागज़ फाड़कर फेंके गए।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 05 फरवरी, 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1702 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 5 फरवरी 2026 / 16 माघ 1947 (शक)
के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।